श्री प्रकाश वीर शास्त्री : संख्या कितनी है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : अभी संख्या कैसे बतला दी जाये । आप उत्तर तो सुन लीजिये । माननीय सदस्य चाहते हैं कि हम उनको कह दें तीन लाख लोगों में से पौने तीन लाख चले गये । हम यह एक दम नहीं कह सकते । हम चाहते हैं कि ऊंचे अफसर भी उन लोगों की दरखास्तों को देख सकें । वे लोग अपील करते हैं और उनको सुनने में समय लगेगा ।

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि हमने बहुत थोड़े लोगों को क्विट नोटिस दिया लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि पिछले दो महीनों में करीब १२ हजार आदमी अपने आप चले गये बगैर गौर किसी नोटिस के । वे लोग इल्लीगल इनफिलट्रेटर थे । उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट की क्या नीति है, इसलिये वे अपने आप चले गये ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि अभी नये लोग भी आ रहे हैं और जो लोग अभी वापस नहीं भेजे जा सके हैं इनको किस तारीख तक वापस भेज दिया जायेगा ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह आना जाना तो दोनों तरफ से लगा रहता है । उधर से मुसलमान इधर आते हैं और इधर से हिन्दू उधर जाते हैं । भारतीय मुस्लिम्स भी उधर जाते हैं ।

Shri Hem Barua: It is a matter of foreign national not Muslims.

श्री लाल बहादुर शास्त्री : और उधर से पाकिस्तानी मुस्लिम आते हैंय।

Some Hon. Members *rose*—

Mr. Speaker: If those infiltrants cannot be restrained there I find that the Members here are also presenting the same difficulty. This is a delicate question. If some facts cannot be given by the hon. Minister, that should not be insisted upon under the present circumstances. I would appeal to hon. Members that there are cases where it is not possible to give every bit of information. For instance, hon. Members cannot insist that the number must be given in this particular case. That is not possible.

National Discipline Scheme

+

*35. Shri Bhakt Darshan:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri M. L. Dwivedi:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri Sonavane:
Shri D. C. Sharma:
Shri B. K. Das:
Shri Subodh Hansda:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri Bade:
Shri Marandi:
Shri Heda:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 436 on the 23rd January, 1963 and state the progress made so far in the implementation of the decision regarding the introduction of National Discipline Scheme in the schools throughout the country.

The Parliamentary Secretary to the Minister of Education (Shri M. R. Krishna): The progress made to-date is as under:—

(i) Two Training Centres for orienting In-Service Physical Education Teachers in the new programme have been set up at Punchkula (Punjab) and Meerut (U.P.) for training 1050 persons;

(ii) Two more Training Centres that are likely to be located at Indore and Rajpipla (Gujarat) for training fresh Instructors under the programme are scheduled to start functioning at a very early date;

(iii) The Syllabi for School students and for orientation courses to teachers under the Emergency Integrated Programme of National Discipline and Physical Education have been worked out.

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के इस उत्तर से यह स्पष्ट है कि जिस तेजी से सारे देश में इस योजना को फैलाने का निश्चय किया गया था उतनी तेजी में सफलता नहीं मिली है तो क्या यह आशा की जा सकती है कि सब से पहले कम से कम सीमावर्ती क्षेत्रों के जो स्कूल हैं उनमें इसे लागू किया जाय और बाद में सब जगह इसे फैलाया जाय ?

Shri M. R. Krishna: There is absolutely no delay on the part of the Ministry. We have to ask the State Governments whether they are willing to have the schemes in their States. We are at the moment training people who are in service, and we are also trying to train nearly 6,000 people fresh for taking up this movement. So there is absolutely no delay on our part.

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, पिछले प्रश्न का उत्तर देते हुये बतलाया गया था कि इस योजना में ए० सी० सी० का भी जो खास कार्यक्रम है उसको सम्मिलित कर लिया जायेगा । लेकिन कुछ ही दिनों बाद यहां एक प्रश्न का उत्तर देते हुये माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने बतलाया कि ए० सी० सी० को शामिल नहीं किया जायगा । मैं जानना चाहता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० श्रीमाली) : इस मामले में डिफेंस मिनिस्टरी और एजुकेशन मिनिस्टरी में मशविरा हो रहा है । स्टेट गवर्नमेंट्स से भी इस मामले में स्लाह ली गई है । परिस्थिति यह है कि हमने राज्य सरकारों को लिखा है कि हम पूरा खर्चा देने को तैयार हैं अगर वह इस स्कीम से फायदा उठाना चाहें । इसलिये अभी तो दोनों स्कीमों को चलाने के लिये गुंजाइश है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे स्कूलों में जितने भी बच्चे हैं उन सबको फिजिकल एजुकेशन का प्रोग्राम मिले चाहे वह नेशनल डिसिप्लन स्कीम के अन्तर्गत हो और चाहे ए० सी० सी० के अन्तर्गत हो । अभी परिस्थिति यह है कि काफी काम करने की गुंजाइश है । वहां काफी तादाद में लड़के लिये जाते हैं और दो, तीन साल तक अगर इसके लिये काम किया जाय तो स्कूलों में इस वक्त दोनों स्कीमें तेजी से विस्तार कर सकती हैं । लेकिन जैसा मैंने बतलाया इ मामले में डिफेंस मिनिस्टरी के साथ मशविरा हो रहा है और मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही कुछ न कुछ निर्णय इस मामले में हो जायगा ।

Shrimati Savitri Nigam: May I know whether the number of trainees who are going to take training in these centres will be sufficient to start the training in States which have accepted this programme?

Shri M. R. Krishna: In addition to those people who are already doing this type of work, there is a scheme to train 6,000 people more, and later on the number may be increased.

Shri Subodh Hansda: I understand from the statement of the Parliamentary Secretary that only four centres have been opened, all of them in Western India. What is the difficulty of Government in opening such centres in eastern India?

Shri M. R. Krishna: We have to open these centres in consultation with State Governments. Some of them like West Bengal and Bihar are not very keen on introducing this scheme there. They want to continue the old ACC and NCC schemes. Therefore, we are not able to start the centres in all the States at this time.

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : राष्ट्रीय अनुशासन योजना की लोकप्रियता और आवश्यकता को अनुभव करते हुए शिक्षा मंत्री महोदय

ने पिछले अधिवेशन में यह बतलाया था कि सरिसका के अतिरिक्त भारतवर्ष के कुछ और महत्वपूर्ण स्थानों पर उसका शिक्षण देने के केन्द्र खोले जायेंगे । क्या मैं जान सकता हूं कि उस संबंध में अन्तिम निश्चय कर लिया गया है, यदि हां, तो उसकी रुपरेखा क्या है ?

डा० श्रीमाली : जी हां, इस बारे में कोशिश की जा रही है कि देश के अन्य भागों में भी यह केन्द्र खोले जांय । पंजाब में झज्जर में एक केन्द्र खोलने की योजना है । राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में एक केन्द्र खोलने का विचार किया जा रहा है । महाराष्ट्र में भी एक केन्द्र खोला जा रहा है । हमारी कोशिश यह है कि हम को ऐसी इमारतें मिल जांय जिस में खर्चा भी ज्यादा न करना पड़े । खाली इमारतें इस तरह की जहां जहां मिल सकती हैं उन को लेने की कोशिश की जा रही है । इस दृष्टि से जगह जगह यह केन्द्र खोले जा रहे हैं और जैसा मैंने आप से निवेदन किया हमारी कोशिश यह है कि स्कूलों में छठी क्लास से ग्यारहवीं क्लास तक एक भी बच्चा ऐसा न रहे जिसको कि यह राष्ट्रीय शारीरिक श्रम का प्रोग्राम उपलब्ध न हो ?

श्री बड़े : क्या यह बात सच नहीं है कि एक प्रश्न के जवाब में शासन ने यह आश्वासन दिया है कि नेशनल डिसिप्लन स्कीम कम्पलसरी की जायगी, यदि हां, तो क्या केन्द्र से इस बारे में मध्य प्रदेश की सरकार को लिखा गया है ?

डा० श्रीमाली : सब को लिखा गया है और सभी का जवाब संतोषजनक है । इस योजना को प्रसारित करने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है । इस योजना के विस्तार के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगभग ६ करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या एन० सी० सी० की योजना से इस में कुछ लाभ नहीं उठाया जा सकता है ?

डा० श्रीमाली : जहां तक एन० सी० सी० का सम्बन्ध है माननीय सदस्य को मालूम है कि इस का कार्यक्षेत्र यूनिवर्सिटीज और कालिजों में है । कहीं कहीं हाई स्कूलों में भी है लेकिन अधिकतर उनका कार्यक्षेत्र युनिवरसिटीज और कालिजों में है । नेशनल डिसिप्लन स्कीम छठी क्लास से लेकर हाई स्कूल तक है ।

Shri H. N. Mukerjee: In view of the fact that the universalisation of the ACC or NCC facilities would necessarily take a fairly considerable amount of time, and also in view of the fact that the National Discipline Scheme has been found to be a very cheap and at the same time efficient method of introducing the ideas of national integration into our children, will Government take some very special steps with regard to a State like West Bengal or Bihar, where it seems some difficulties are being experienced in the introduction of this scheme?

Dr. K. L. Shrimali: I am aware that this scheme has been generally liked and welcomed by the Members of Parliament and by the people outside also. Every effort is being made by the Government to expand the scope of the scheme, and, as I said, we are discussing the matter with the Defence Ministry about the scope of the ACC and the National Discipline Scheme, and as soon as some final decision can be taken, arrangements will be made to introduce physical education on a compulsory basis in all the educational institutions right from the sixth to the eleventh standards; and, of course, NCC is being extended in the universities.

Coordination of Scientific Research

\+

*36. **Shri Surendra Pal Singh:**
Shri Subodh Hansda:
Shri S. C. Samanta:
Shri B. K. Das:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri Rameshwar Tantia:
Shri Bishanchander Seth: